LOK SABHA

Tuesday, August 1, 1967/Sravana 10, 1889 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Abolition of District Boards

+

***1501. Shri Bibhuti Mishra:**
Shri K. N. Tiwary:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have issued any directions to the State Governments for the abolition of District Boards;

(b) if so, when and the broad outlines thereof;

(c) the names of the States which have abolished the District Boards and those wherein they continue to exist; and

(d) the alternative machinery devised by Government consequent on the abolition of these Boards to give representation to the rural people in the administration of matters of local importance?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) District Boards do not exist in any State, except in 14 Districts of Bihar.

(d) The three-tier Panchayati Raj structure which has come into being in all the States except Madhya Pradesh, parts of Bihar, Kerala, Nagaland and Jammu and Kashmir, has replaced the District Boards and provided representation to the rural people in local development administration.

श्री विभूति मिश्र: अध्यक्ष महोदय, संविधान में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का स्थान है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ज़रिये कांसिल के मेम्बर चुने जाते हैं। बिहार में 10 वर्षों से पहले से वहां की गवर्नमेंट ने इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को तोड़ दिया, जिस की वजह से गांववालों का कान्सिल में जो डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की मारफत रिप्रेज़ेन्टेशन होता था, वह बन्द हो गया।

दूसरी बात—गांव के छोटे मोटे काम, दवाई के अथवा सड़कों आदि के वे सब बंद हो गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब हमारे संविधान में इसके लिये स्थान है तो केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कौन सी कार्यवाही की है?

Shri M. S. Gurupadaswamy: It is true that in all the areas district boards have not been abolished, but the powers of the district boards have been taken over by Government, and all the State Governments have accepted the main recommendation of the Balwantray Mehta Committee, and it is our view that as early as possible the three tier system which has

been accepted by all the States should be introduced.

श्री विभूति मिश्र: अध्यक्ष महोदय, संविधान के आर्टिकल 171 में लिखा है कि—

"Of the total number of members of the Legislative Council of a State—

(a) as nearly as may be, one-third shall be elected by electorates consisting of members of municipalities, district boards and such other local authorities in the State as Parliament may by law specify."

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम): जिला परिषद हो गया।

श्री विभूति मिश्र: जिला परिषद नहीं हुआ। सवाल यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जिक्र है, डिस्ट्रिक्ट मूनिस्पैलिटी का जिक्र है, उस को आपने एबोलिश कर दिया, उसकी जगह आपने कुछ नहीं दिया, जब कि कांस्टीचूशन में लिखा है कि इन का रिप्रेजेन्टेशन होगा। मैं जानना चाहता हूं कि जब कांस्टीचूशन की रक्षा की कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के हाथ में है, तो केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या किया और गांव वालों का जो हक था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मारफ़त उसके आदमी कान्सिल में जाते थे, उसको बन्द कर दिया और वह 10 वर्ष से बंद है—इस लिये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गांववालों का जो हक था, उसके प्रोटेक्शन के लिये केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है?

Shri M. S. Gurupadaswamy: It is for the Election Commission indeed to take up this issue, and so far as we are concerned, we would like to have the three tier system of Panchayati Raj established in all the States, and that will really provide not only the local administration but also the members in those bodies will participate in the election. But as it is in Bihar, in those 14 districts, there are no district Boards. Technically there are district boards, but there are no members functioning there. So, I would appeal to the hon. member to use his good offices with the Ministry there and see that these institutions are established as early as possible.

श्री विभूति मिश्र: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। यह मंत्री जी का काम है कि साफ साफ जवाब दें। हम अपने गुड आफिसिज़ कैसे इस्तेमाल करेंगे... व्यवधान.....यह तो केन्द्रीय मंत्रालय का कर्त्तव्य है कि संविधान की रक्षा करें। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सवाल पहले ला मिनिस्ट्री में था, वहां से होम मिनिस्ट्री में गया, वहां से ट्रांसफर हो कर यहां चला आया, तीन महीने से हमारा यह सवाल घूमता रहा, घूमने के बाद अब यह कहते हैं कि अपने गुड आफिसिज़ को इस्तेमाल करो, अगर हमें गुड आफिसिज़ का इस्तेमाल करना है तो यह यहां किस लिये हैं?

Shri Jagjiwan Ram: Perhaps we have already written to the State government concerned to introduce the three tier system as early as possible.

Shri Bibhuti Mishra: By what time will they come into effect? I want to know that. Ten years have already elapsed. यह कब इफेक्ट में आयेगा?

अध्यक्ष महोदय: यह सवाल तिवारी जी पूछ सकते हैं।

Shri M. S. Gurupadaswamy: They have taken some time; the Government of Bihar has extended the period up to March 1968. They propose to introduce the three tier system soon after that date is over.

श्री क० ना० तिवारी: जैसा मंत्री जी ने कहा कि पंचायत राज्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जगह पर आयेगा तथा यह भी बताया कि वहां

की सरकार ने इस के लिये समय मांगा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या ग्राम पंचायतों का चुनाव नई सरकार आने के बाद अपने मन से कराना चाहती है तथा इस लिये समय मांगा है कि जिसमें उन के मन के मुताबिक जिला परिषदें बन सकें तथा क्या इसीलिये देरी हो रही है ?

Shri M. S. Gurupadaswamy: It is our desire that the new Bihar government should take up this matter quickly, but as I said earlier they have extended the period till March 1968. We hope that soon after this date is over, there will be three tier system coming into operation in Bihar.

श्री क० न० तिवारी: जब ग्राम पंचायतों का चुनाव हो गया है और ग्राम पंचायतें मिल कर जिला परिषदें बनायेंगी तो फिर बिहार गवर्नमेंट ने जो 1968 तक का टाइम मांगा है, क्या इस का यह मतलब है कि वे फिर से अपने नये तरीके से चुनाव कराना चाहती हैं ताकि उन के मन के मुताबिक जिला परिषदें बन सकें और इसी लिये देरी हो रही है। इस संबंध में भारत सरकार की जानकारी क्या है तथा उस पर वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगजीवन राम: कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन जिन पंचायतों की अवधि पूरी हो जायगी, उन का नया चुनाव होगा, अवधि पूरी नहीं होगी तो चुनाव नहीं होगा। लेकिन यह बात सही है कि नई सरकार के आने के बाद बिहार में सूखे की वजह से जो स्थिति रही, शायद उस में चुनाव कराने की बात सोचना कुछ मौजूं नहीं था।

Shri Dinkar Desai: In Mysore State there are no district boards but there are district school boards for primary school administration and the government nominates its members. That is an undemocratic procedure. May I know whether the Central government will take up this question with the Mysore government and give them directions so that the district boards may be elected bodies and not nominated bodies?

Shri M. S. Gurupadaswamy: That question does not arise; this relates to Bihar.

डा० राम मनोहर लोहिया: अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल सारे भारत के लिये है और अगर निर्वाचन बनाम नियुक्ति के सिद्धांत पर सरकार ने ध्यान दिया है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस पर सोचा है कि जिलाधीशों अथवा कलैक्टरों को बिलकुल खत्म कर दिया जाय और उनकी जगह पर कोई निर्वाचित शक्ति या अधिकार बनाया जाय ? यदि सोचा है तो क्या नतीजा निकला और यदि नहीं सोचा है तो क्यों नहीं सोचा ?

श्री जगजीवन राम: उन्होंने अभी जवाब दिया है कि जिन जिन जगहों पर यह चुनाव नहीं हुए हैं, वहां हम ने बराबर तकाजा किया है कि चुनाव जल्द करा लेना चाहिये और जैसा कि उन्होंने बताया कि बिहार के कुछ जिलों और जगहों पर चुनाव नहीं हो सका, वहां चुनाव नहीं हुए हैं। ....

श्री मधु लिमये: वे तो कलैक्टरशाही और नौकरशाही के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री जगजीवन राम: जी हां, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। ....

श्री मधु लिमये: वह कह रहे हैं कि कलैक्टरशाही खत्म करो, सारे अधिकार जिला पंचायतों के हाथ में दो।

श्री जगजीवन राम: मैंने जवाब खत्म नहीं किया है, लेकिन आप लोगों को इल्हाम हो गया और पहले से बोलने लगे। जहां चुनाव नहीं हुआ है, जिला बोर्ड खत्म हो गया है, जिला बोर्ड के सारे फंक्शन कलैक्टर के हाथ में दिये हुए हैं। यही मैंने कहा है कि बार बार हम तकाजा करते हैं कि उसका चुनाव कर के निर्वाचित अधिकारी को लाना चाहिये।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, यह उलटी गंगा बहाई। मेरा सवाल था कि यह निर्वाचन बनाम नियुक्ति के सिद्धान्त पर सोच विचार करते हुए क्या सरकार ने कभी सोचा है कि जिलाधीशों और कलक्टरों को बिलकुल खत्म ही कर दिया जाय और उन के जितने अधिकार हैं जिला परिषद या कोई और संस्था जो आप के दिमाग में आये उन को दे दीजिये, अगर सोचा है तो क्या नतीजा निकला और अगर नहीं सोचा है तो क्यों नहीं सोचा?

श्री जगजीवन राम : जनाब यह इस प्रश्न के दायरे के भीतर की बात नहीं है। जिस प्रश्न को आप ने उठाया है उस प्रश्न का सीधा सम्बन्ध लोकल बौडीज के साथ साथ है और जहां तक लोकल बौडीज का सम्बन्ध है उस में यह मामला साफ़ है कि जिला अधिकारी को उस का हैड नहीं होना चाहिए और वह निर्वाचित लोगों के हाथ में होना चाहिए।

डा० राम मनोहर लोहिया : फिर देखिये अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। आप मेहरबानी करके मंत्री महोदय को बतलाइये।

Mr. Speaker: If I have understood him properly, the State Governments have authorised the district boards; they could take decisions.

डा० राम मनोहर लोहिया : मेरा मतलब यह नहीं है। मेरा मतलब तो यह है कि कलैक्टर रहना ही नहीं चाहिए। यह सवाल है। क्या कभी सोचा है इन्होंने, अगर सोचा है तो क्या नतीजा निकला और अगर नहीं सोचा हो तो क्यों नहीं सोचा है?

Shri Jagjiwan Ram: What I have said is that it does not come within the jurisdiction of this question.

Mr. Speaker: He said that the department is not concerned with this matter at all. Shri Venkatasubbaiah.

Shri P. Venkatasubbaiah: While replying to the question earlier, the Minister said that the recommendations of the Balwantray Mehta Committee have been introduced in all the States except in Bihar. You are aware that under your stewardship, Andhra Pradesh was the first State to introduce the Balwantray Mehta Committee's recommendations. I would like to know whether the Government has taken any steps to introduce a uniform system so far as the recommendations of the Balwantroy Mehta Committee's report is concerned, because it varies from State to State. I want to know whether Government proposes to give instructions to the State Governments to introduce a uniform system in this regard.

Shri M. S. Gurupadaswamy: The approach is to have a certain broad pattern and agreement on fundamentals. A certain amount of flexibility is given to the States to introduce their own forms and patterns. So, within the broad pattern, they are free to have their own forms and patterns.

Shri Ranga: May I know whether it is not a fact that this question falls within the special purview of the State Governments and it is not a concurrent subject, and the Union Government has no power to give directions? Secondly, may I know whether it is not a fact that in many States the District Boards themselves have advised their own respective governments to entrust more and more of the functions dealing with grow more food and other things to the Collectors—even the distribution of foodgrains also to the Collectors—rather than to the so-called elected panchayat samitis?

Shri M. S. Gurupadaswamy: The Balwantray Mehta Committee was set up by the Planning Commission and the recommendations of this Committee are meant to be followed by the State Governments. The State

Governments are at liberty to accept these recommendations. As a matter of fact, the National Development Council, at its meeting in 1958, endorsed the main recommendations of the Balwantray Mehta Committee and they accepted them. Therefore, various States have taken steps to introduce the panchayat raj system. So, there is no question of imposition on the States.

Shri P. Venkatasubbaiah: What does the hon. Member mean by saying "so-called elected panchayat samitis"?

श्री प्रेम चन्द वर्मा : मुल्क में जिला बोर्ड और जिला परिषद दो प्रकार की पद्धतियां हैं लेकिन कई जगह पर जो जिला परिषद हैं उन के चेअरमैन एलैक्टिड हैं जबकि कई अन्य राज्यों में जिला परिषद के ऐक्स-ओफिशियो चेअरमैन डिप्टी कमिश्नर हैं तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह जो पंचायती राज्य बनाया गया है उस में सरकार ने दो प्रकार की पद्धतियां क्यों रक्खी हैं ? जिला परिषद का चेअरमैन एलैक्टिड होना चाहिए या डिप्टी कमिश्नर ऐक्सओफिशियो उसका चेअरमैन होना चाहिए, सरकार का इस के बारे में क्या उत्तर है ?

Shri M. S. Gurupadaswamy: I have already replied to this question. We lay down a broad pattern for the States to follow. But some States have elected Chairmen and the Zila Parishad; and in some other States there is the district advisory council. The Panchayat Samitis are really an important link. We have left to the States to adopt the pattern they would like to have.

Shri Ranga: There is no question of leaving.

श्री प्रेम चन्द वर्मा : मैं ने जो पूछा है उस का उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया कि उन की इस बारे में क्या राय है ?

Shri M. S. Gurupadaswamy: The three-tier system is adopted by most of the States. But we give them flexibility and manoeuvrability and each State is free to adopt certain changes within the broad framework that has been evolved.

Shri Shri Chand Goel: Considering this three-tier system and considering also that universal adult franchise has been introduced and all people are given representation, I want to know how far this three-tier system has succeeded in developing initiative and drive and also developmental activities. Has the Government carried out any assessment in order to judge the work of this three-tier system whether it has succeeded in developing initiaive and drive and also interest in developmental activities in the rural population?

Shri M. S. Gurupadaswamy: The panchayati-raj institution has given opportunity and scope for the people to participate not only in the local administration but also in developmental activities, and the reports we have been receiving are quite encouraging. Wherever these institutions operate and exist the involvement and commitment of people in various activities is very much in the picture. Therefore, I say that this pattern should be adopted in all the other areas where panchayati-raj institutions have not been formed so far. It is our desire that it should cover the whole of India.

Equipment for Digging Tube-Wells

+

*1502. **Shri Madhu Limaye:**
Shri S. M. Banerjee:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri George Fernandes:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the wide differences in the number of tube-wells in the various States;

(b) whether Government's attention has been drawn to the acute shortage